भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5362

05 अप्रैल, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: वैकल्पिक न्यूनतम कर

5362. डॉ. जयंत कुमार राय:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री राजा अमरेश्वर नाईक:
डॉ. सुकान्त मजूमदार:
श्री भोला सिंह:
श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या):
श्री विनोद कुमार सोनकर:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर कम कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में सहकारी समितियों जिनकी कुल आय 1 करोड़ रूपये से अधिक और 10 करोड़ रूपये तक है के मौजूदा सरचार्ज को 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सहकारी समितियों और इसके सदस्यों जो ज्यादातर ग्रामीण और कृषक समुदायों से हैं की आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) एवं (ख): जी हां। भारत सरकार ने बजट 2022-23 में सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर (एमएटी) को 18.5 प्रतिशत कम करके 15 प्रतिशत करने तथा उन सहकारी समितियों के लिए, जिनकी कुल आय 1 करोड़ से अधिक तथा 10 करोड़ रूपए तक है, पर सरचार्ज को 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया है।

(ग): सरकार ने देश में सहकारी आंदोलन को सुदृढ़ करने के लिए अलग प्रशासनिक, कानूनी एवं नीतिगत फ्रेमवर्क प्रदान करने के लिए नए सहकारिता मंत्रालय का सृजन किया है। सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों/केंद्र सरकार, राज्य सरकार के विभागों, सहकारी संघ इत्यादि सहित विभिन्न हितधारकों के परामर्श से एक नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति तथा नई स्कीमों को तैयार करने के लिए भी कदम उठाने की पहल की है।

*****